



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.- 31032021-226278  
CG-DL-E-31032021-226278

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 110]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 2021/चैत्र 10, 1943

No. 110]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 2021/CHAITRA 10, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2021

मामला संख्या: एडी (एसएसआर) -05/2021

**विषय: चीन जन.गण., जापान, कोरिया आर.पी., रूस, ब्राजील और इंडोनेशिया से "अलॉय या नॉन-अलॉय स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों" के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत।**

**फा. सं. 7/5/2021-डीजीटीआर.—**1. इंडियन स्टील एसोसिएशन (जिन्हें यहां आगे "आवेदक" या "याचिकाकर्ता" भी कहा गया है) ने चीन जन.गण., जापान, कोरिया आर.पी., रूस, ब्राजील और इंडोनेशिया (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "अलॉय या नॉन-अलॉय स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों" के आयातों के संबंध में (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत के लिए समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, आकलन तथा पाटनरोधी शुल्क के संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण हेतु)

नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसरण में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जे एस डब्ल्यू स्टील लिमिटेड और आर्सेलर मित्तल निप्पोन स्टील इंडिया लिमिटेड (जिन्हें आगे "आवेदक उत्पादक" भी कहा गया है) की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है। आवेदक उत्पादकों ने आवेदन में निर्धारित सूचना उपलब्ध कराई है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि पाटनरोधी शुल्क को लगाने के पश्चात भी संबद्ध देशों से पाटन जारी है और शुल्कों को समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति की संभावना है। आवेदक ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर शुल्कों के विस्तार के लिए अनुरोध किया है।

### **पृष्ठभूमि**

3. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में मूल पाटनरोधी जांच निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा 11 अप्रैल, 2016 को आरंभ की गई थी। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 1 अगस्त, 2016 की प्रारंभिक जांच परिणामों के अनुसार अनंतिम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की थी जिसे दिनांक 8 अगस्त, 2016 की अधिसूचना सं. 44/2016-सीमाशुल्क के अनुसार लागू किया गया था। विस्तृत जांच के अनुसरण में, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/09/2016-डीजीएडी दिनांक 10 अप्रैल, 2017 के अनुसार संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर संदर्भ कीमत के रूप में निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्कों को लागू करने की सिफारिश की थी। निर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिशों को 8 अगस्त, 2016 से प्रभावी कर पांच वर्षों की अवधि के लिए अधिसूचना सं. 17/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 11 मई, 2017, (दिनांक 16 मई, 2017 को परिशोधन द्वारा यथासंशोधित) के अनुसार क्रियान्वित किया गया था। वर्तमान शुल्क 8 अगस्त, 2021 को निरस्त होंगे।

### **विचाराधीन उत्पाद**

4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (जिसे आगे "पीयूसी" कहा गया है) 2100 मि. मि. तक की चौड़ाई वाले और 25 मि.मि. तक की मोटाई वाले कॉयलों में अलॉय या नान अलाय स्टील के हॉट रोलड फ्लैट उत्पाद और 4950 मि.मी. चौड़ाई और 150 मि.मी. तक मोटाई के और कायलों के बिना अलॉय या नॉन-अलाय स्टील के हॉट रोलड फ्लैट उत्पाद (आम तौर पर शीट और प्लेट्स के रूप में ज्ञात) हैं।
5. निम्नलिखित विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल नहीं हैं :-
  - (क) स्टेनलैस स्टील के हॉट रोलड फ्लैट प्रोडक्ट।
  - (ख) स्टील के हॉट रोलड फ्लैट प्रोडक्ट जो इलैक्ट्रोलीटिकली प्लेटिड या जिंक से कोटिड हैं।
  - (ग) अन्यथा रूप से प्लेटिड या जिंक से कोटिड स्टील के हॉट रोलड फ्लैट प्रोडक्ट।
  - (घ) क्लेडेड स्टील।
6. पीयूसी में ऐसे उत्पाद शामिल हैं जो हॉट रोलड की तुलना में आगे काम नहीं करते हैं और जो "एस रोलड" किनारे या "ट्रिम्ड" किनारे या "स्लिट" किनारे या "माइलड" किनारे या "शियर्ड" किनारे या "लेजर कट" किनारे या "गैस कट" किनारे या किसी अन्य प्रकार के किनारों वाले प्राइम या नान प्राइम स्थिति में ऑयरन, अलॉय या नान अलाय स्टील के फ्लैट प्रोडक्ट हैं। ये उत्पाद पिकलड या नॉन-पिकलड (स्किन पास या टेंपरिंग के साथ अथवा उसके बिना), स्लिट या नॉन-स्लिट, नार्मलाइज्ड या अन-नार्मलाइज्ड, अल्ट्रा-सोनीकली परीक्षण किया गया या परीक्षण न किया गया अथवा आयलड या नॉन ऑयलड आदि हो सकते हैं। ये उत्पाद "एज रोलड" अथवा "थर्मो-मेकेनिकली रोलड" अथवा "थर्मोमैकेनिकली कंट्रोलड रोलड" अथवा "कंट्रोलड रोलड" "नार्मलाइज्ड रोलड" या "नार्मलाइज्ड" अथवा किसी अन्य समान प्रक्रिया के अधीन हो सकते हैं। ये उत्पाद हॉट रोलिंग के दौरान सीधे ही व्युत्पन्न विभिन्न प्रकारों के रिलीफ/चैकर्ड पैटर्न में हो सकते हैं। ये उत्पाद विभिन्न प्रसंस्करण चरणों के अधीन हो सकते हैं जैसे पिकलिंग, ऑयलिंग, रिवाइंडिंग, रिक्वायलिंग, टेंपर रोलिंग, हीट ट्रीटमेंट, आदि। ये उत्पाद सैंड ब्लास्टिड या

शॉट ब्लास्टिड या समान प्रक्रियाओं के अध्यक्षीन हो सकते हैं। पीयूसी में अलॉय या नॉन अलाय स्टील की हॉट रोलड फ्लैट शीट्स और प्लेट्स, यूनिवर्सल प्लेट मिल से रोलड की गई अथवा न की गई यूनिवर्सल प्लेट मिल जिसमें रिवर्सिबल प्लेट मिल या हॉट स्ट्रिप मिल या टैंडेम मिल या स्टीकल मिल 2-हाई, 3-हाई, 4- हाई सहित विभिन्न प्रकार के रोलिंग कान्फ्यूगरेशन सहित कोई अन्य समान प्रक्रिया, क्लस्टर मिल या कोई अन्य समान हॉट रोलिंग प्रक्रिया, शामिल हैं। पीयूसी में या तो सीधे हॉट रोलिंग प्रक्रिया से उत्पादित अथवा हॉट रोलड कॉयल्स से काटी/कतरी गई शीटें और प्लेट्स शामिल हैं।

7. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में विचारधीन उत्पाद का क्षेत्र वही है जैसा कि मूल जांच में है।
8. पीयूसी का प्रयोग बहुत से अनुप्रयोजनों और क्षेत्रों में किया जाता है जैसे आटोमोटिव, ऑयल और गैस लाइन पाइप्स एक्सप्लोरेशन, कोल्ड रोलिंग, पाइप और ट्यूब विनिर्माण, बुनियादी ढांचा और निर्माण, सामान्य इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन, अर्थ-मूविंग और माइनिंग उपकरण, स्टोरेज टैंक, लो प्रेशर हीटर्स, कैपिटल वस्तुएं जिनमें सीमेंट, खाद, रिफाइनरी आदि के लिए संयंत्र और प्रक्रिया शामिल हैं।
9. पीयूसी को सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष 7208, 7211, 7225 और 7226 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं हैं।
10. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने निर्णायक समीक्षा याचिका में पीसीएन कार्य पद्धति का प्रस्ताव नहीं किया है। तथापि, यह नोट किया गया है कि मूल जांच में, घरेलू उद्योग द्वारा पी सी एन कार्य पद्धति का प्रस्ताव किया गया था और प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन के परिकलन के लिए पीसीएन से पीसीएन की तुलना करने के लिए उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) का निर्धारण किया है। मूल जांच में निर्धारित पी सी एन नीचे दिए गए हैं और इसका वर्तमान निर्णायक समीक्षा के लिए प्रस्ताव किया गया है।

हॉट रोलड फ्लैट स्टील उत्पादों के लिए पीसीएन				
क्र.सं..	विशेषता	अंकों की संख्या	विवरण	कोड
1	उत्पाद प्रकार	1	कॉयल	ग
			कट टू लैथ स्लिट, शीट, प्लेट्स	ठ
			प्लेट मिल प्लेट	त
2	गुणवत्ता	4	कोल्ड रोलिंग/गॉल्वेनाइजिंग क्वालिटी	थ 01 थ
			पाइप एवं ट्यूब क्वालिटी	थ 02 थ
			एच एस एल ए सहित उच्च टैंसिल	थ 03 थ
			उच्च शक्ति वाला संरचनात्मक स्टील(वाईएस 350 एमपीए एवं अधिक)	थ 04 थ
			संरचनात्मक स्टील (350 एमपीए से निम्न वाई एस)	थ 05 थ
			चैकर्ड क्वालिटी	थ 06 थ

हॉट रोल्ड फ्लैट स्टील उत्पादों के लिए पीसीएन				
क्र.सं..	विशेषता	अंकों की संख्या	विवरण	कोड
			ड्राइंग/फारमिंग/फ्लैगिंग क्वालिटी स्टील	थ 07 थ
			एपीआई ग्रेड X52 और उच्च क्वालिटी स्टील	थ 08 थ
			एक्स 52 क्वालिटी से निम्न के एफपीआई ग्रेड के स्टील	थ 09 थ
			क्वेचड/टेम्पर्ड क्वालिटी	थ 10 थ
			कोरोजन रेसिस्टेंट स्टील क्वालिटी	थ 11 थ
			बॉयलर/प्रेसर वेसल क्वालिटी	थ 12 थ
			शिप बिल्डिंग क्वालिटी	थ 13 थ
			एलपीजी सिलेंडर क्वालिटी	थ 14 थ
			मीडियम/हाई कार्बन स्टील क्वालिटी	थ 15 थ
			सिलीकॉन इलैक्ट्रिकल स्टील	थ 16 थ
			उपर्युक्त में अन्य क्वालिटी शामिल नहीं हैं	थ 17 थ
3	मोटाई	1	1.6 मि.मि. तक	न
			16 मि.मि. से अधिक 2 मि.मि. तक	प
			2 मि.मि. से अधिक 10 मि.मि. तक	फ
			10 मि.मि. से अधिक 25 मि.मि. तक	ब
			25 मि.मि. से अधिक 40 मि.मि. तक	भ
			40 मि.मि. से अधिक 100 मि.मि. तक	त
			100 मि.मि. से अधिक 150 मि.मि. तक	य
4	चौड़ाई	1	600 मि.मि. तक	1
			600 मि.मि. से अधिक 1500 मि.मि. तक	2
			1500 मि.मि. से अधिक 2500 मि.मि. तक	3
			2500 मि.मि. से अधिक 300 मि.मि. तक	4

हॉट रोल्ड फ्लैट स्टील उत्पादों के लिए पीसीएन				
क्र.सं..	विशेषता	अंकों की संख्या	विवरण	कोड
			3000 मि.मि. से अधिक 4950 मि.मि. तक	5
5	अनुदैर्घ्य (लॉंगिट्यूडनल) किनारे	2	लपेटा हुआ	ड.ख
			शियर्ड/ट्रिम्ड/माइलड/गैस-कट आदि	ड.घ
6	सतह उपचार/सतह तैयारी	1	पिकल्ड	ज
			सैंड-ब्लास्टिड/शॉट ब्लास्टिड	झ
			पेटेड	ट
			कोई सतह उपचार नहीं/कोई सतह की तैयारी नहीं	ठ
7	हीट ट्रीटमेंट	1	असामान्यीकृत	8
			सामान्य	9
उदाहरण: चैकर्ड क्वालिटी की एक प्लेट मि.मि. प्लेट/असामान्यीकृत हीट ट्रीटमेंट वाले पिकल्ड फार्म में शियर्ड किनारों के साथ 750 मि.मि. चौड़ाई वाले 80 मि.मि. मोटाई वाला उत्पाद पीसीएन होगा : PQ06QY2EDH8(11 अंक)				

11. हितबद्ध पक्षकार जांच शुरूआत नोटिस की तारीख से 10 दिन के भीतर पीसीएन कार्य प्रणाली पर अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हो, प्रस्तुत कर सकते हैं।

#### समान वस्तु

12. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु भारत को संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के समान हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं तकनीकी विशेषताएं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की शर्तों में संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं के तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए, इन्हें नियमावली के अंतर्गत 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। इसलिए वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के 'समान वस्तु' माना जा रहा है।

**घरेलू उद्योग**

13. आवेदन को घरेलू उत्पादकों की ओर से भारतीय स्टील एसोसिएशन (आवेदक) द्वारा दायर किया गया है। निम्नलिखित आवेदक उत्पादकों ने निर्णायक समीक्षा जांच के प्रयोजनार्थ अपनी लागत निर्धारण और क्षति संबंधी सूचना उपलब्ध कराई है :-
- क. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड,
- ख. जे एस डब्ल्यू स्टील लिमिटेड
- ग. आर्सिलर मित्तल निप्पोन स्टील इंडिया लिमिटेड
14. आवेदन को (i) टाटा स्टील लिमिटेड और (ii) टाटा स्टील बी एस एल लिमिटेड द्वारा समर्थन प्राप्त है।
15. तीन आवेदक उत्पादकों में से, जे एस डब्ल्यू स्टील लिमि. और आर्सिलर मित्तल स्टील निप्पोन इंडिया लिमि. ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की कम मात्रा आयात की है। चूंकि उनके द्वारा आयातित मात्रा कम है और उनका प्रचालन का केन्द्र और क्षेत्र घरेलू समान वस्तुओं का विनिर्माण करना तथा संबद्ध वस्तुओं की ट्रेडिंग में शामिल न होना जारी रहेगा। प्राधिकारी ने उन्हें घरेलू उद्योग के भाग के रूप में मानना सही समझा है।
16. एस्सार स्टील इंडिया लि. द्वारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अहमदाबाद द्वारा पारित दिनांक 02.08.2017 के एक आदेश द्वारा निगमित दिवालियापन परिशोधन प्रक्रिया लागू की गई थी। दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 द्वारा स्थापित कार्य प्रक्रिया के अनुसरण में, आर्सिलर इंडिया प्रा. लि. सफल परिशोधक आवेदक बन गया है और 16.12.2019 से इस कंपनी की संपूर्ण शेयरधारित अधिग्रहित कर ली है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा एक नया निगमन प्रमाण पत्र जारी किए जाने के अनुसरण में, 08.01.2020 से एस्सार स्टील इंडिया लि. का नाम परिवर्तित कर आर्सिलर मित्तल निप्पोन स्टील इंडिया लि. कर दिया गया। कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत कंपनी भारत में निगमित है। यह हॉट रोल्ड प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स (काँयल और गैर-काँयल दोनों में) और कोल्ड रोल्ड प्रोडक्ट्स का घरेलू उत्पादक है और इसकी भारत में महत्वपूर्ण उत्पादन क्षमताएं हैं तथा और अधिक विस्तार की प्रक्रिया चल रही है। मै. निप्पोन स्टील और सुमिटोमो मेटल कॉरपोरेशन, जापान की आर्सिलर मित्तल निप्पोन स्टील इंडिया लिमि. में कोई सीधी शेयरधारिता नहीं है किंतु बहुत सी मध्यवर्ती स्वतंत्र निगमित उद्यमों द्वारा पृथक की गई एक मध्यवर्ती धारक कंपनी में एक अल्पसंख्यक शेयरधारक है। आर्सिलर मित्तल निप्पोन स्टील इंडिया लिमि. ने पी ओ आई के दौरान निप्पोन स्टील और सुमिटोमो मेटल कॉरपोरेशन, जापान से संबद्ध वस्तुएं आयात नहीं की हैं। आर्सिलर मित्तल निप्पोन स्टील इंडिया लि. एक स्वतंत्र, व्यावसायिक रूप से प्रबंधित कंपनी है और इसके शेयरधारकों के वैयक्तिक हित को नहीं दर्शाती। घरेलू उत्पादक के रूप में, यह तथ्य कि यह वर्तमान निर्णायक समीक्षा की मांग करने के लिए अन्य घरेलू उत्पादकों के साथ एकजुट है, इस बात का प्रमाण है कि यह अन्य घरेलू उत्पादकों से अलग तरीके में कार्य नहीं कर रहा है।
17. इसलिए प्राधिकारी का विचार है कि यह संबंध भारत में समान वस्तु के उत्पादक के रूप में आर्सिलर मित्तल निप्पोन इंडिया लिमिटेड के मूल चरित्र को प्रभावित नहीं कर रहा है। इसलिए प्राधिकारी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग के पात्र संघटक के रूप में आर्सिलर मित्तल निप्पोन स्टील इंडिया कंपनी पर विचार करते हैं।
18. रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, आवेदक भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन में प्रमुख समानुपात के लिए उत्तरदायी है। उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी ने आवेदक उत्पादकों को नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थों के भीतर घरेलू उद्योग मानते हैं।
19. यह नोट किया गया है कि आवेदक उत्पादक समर्थकों सहित, कुल घरेलू उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक भाग के लिए उत्तरदायी है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, और उचित जांच के पश्चात प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) की शर्तों के पात्र घरेलू उद्योग हैं और आवेदन ऊपर दी गई नियमावली के नियम 5(3) की शर्तों में स्थिति के मापदंड को पूरा करते हैं।

**कथित पाटन का आधार****सामान्य मूल्य****चीन जन.गण.**

20. आवेदक ने दावा किया है कि चीनी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य को चीन में लागू घरेलू बिक्री कीमतों या लागतों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, केवल तभी यदि उत्तर प्रस्तुत करने वाले चीनी उत्पादक यह प्रदर्शित करते हैं कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार प्रचालित सिद्धांतों पर आधारित है और ए डी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 1 से 6 की शर्तों में उचित तुलना के लिए अनुमति देते हैं और यदि चीनी उत्पादकों में से कोई भी यह प्रदर्शित करने में समर्थ नहीं होता कि वे बाजार अर्थव्यवस्था सिद्धांतों के तहत प्रचालन कर रहे थे तो चीनी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
21. आवेदक ने दावा किया है कि भारत सहित अन्य देशों को ऐसे तीसरे देश से कीमत, बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य को निर्धारित करने के प्रयास किए गए थे। हालांकि, आवेदक इसके संबंध में विश्वसनीय सूचना प्राप्त नहीं कर सका। आवेदक ने दावा किया है कि पीयूसी के विभिन्न ग्रेड हैं और इन्हें बहुत से एच एस कोडों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और इन कारणों से इसके संबंध में सही विश्वसनीय सूचना प्राप्त करना कठिन हो गया है।
22. इसलिए, आवेदक ने नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार “किसी अन्य उचित आधार” के आधार पर चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य निर्धारण किया है। इस संबंध में, आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य को (क) कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमत (ख) घरेलू उद्योग के खपत संबंधी मानदंडों, परिवर्तन लागतों और घरेलू उद्योग के अनुभव के आधार पर एस जी ए लागतों, और (ग) उचित लाभ के आधार पर दावा किया है।

**सामान्य मूल्य ब्राजील, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया आर.पी. और रूस**

23. आवेदक ने दावा किया है कि वे ब्राजील, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया आर.पी. और रूस में संबद्ध वस्तुओं की घरेलू कीमतों के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य या विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने में समर्थ थे। इस तथ्य के कारण भी कि पी यू सी के कई ग्रेड हैं और पीयूसी को 8 अंकीय स्तर पर कई एच एस कोडों के तहत वर्गीकृत किया गया है, एक उचित तीसरे देश की निर्यात कीमत प्राप्त नहीं किया जा सका।
24. उपर्युक्त पर विचार करते हुए और आवेदक के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर, निम्न को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य को निर्धारित किया गया है (क) कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें (ख) अन्य विनिर्माण संबंधी लागतें, परिवर्तन लागत और घरेलू उद्योग के अनुभव के आधार पर एस जी ए व्यय, और (ग) ब्राजील, चीन जन.गण., इंडोनेशिया, कोरिया आर.पी. और रूस के लिए उचित लाभ मार्जिन।
25. जांच शुरुआत के प्रयोजन से, प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा दावा किए गए सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

**निर्यात कीमत**

26. जांच की अवधि के दौरान ब्राजील, इंडोनेशिया और रूस में कॉयल्स के बिना में एच आर के कोई आयात नहीं किए गए और ब्राजील और रूस से कॉयल्स एच आर का कोई आयात नहीं किया गया। निर्यात मूल्य जहां भी वह उपलब्ध है, उसे वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) के सौदावार आयात आकड़ों के आधार पर आवेदन में प्रस्तुत किया गया है। कीमत समायोजन समुद्री भाड़ा, अंतरदेशीय मालभाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभारों, पत्तन एवं संभाल व्ययों एवं गैर-वापसी योग्य वैट (केवल चीन जन गण के मामले में) के कारण किए गए हैं।

**पाटन मार्जिन**

27. ऊपर निर्धारित किए गए अनुसार सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है बल्कि महत्वपूर्ण भी है। इसके प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से उच्च हैं, जिससे यह इंगित होता है कि संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं का पाटनरोधी शुल्क के प्रवृत्त होने के बावजूद पाटित कीमतों पर निर्यात किया जाना जारी है।

**पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना**

28. जारी महत्वपूर्ण आयात मात्राओं, वैश्विक स्टील क्षमता में वृद्धि, भारत के अलावा पूरे विश्व में निम्न स्टील मांग, संबद्ध देशों में महत्वपूर्ण अप्रयुक्त क्षमताओं, संबद्ध देशों के विरुद्ध अन्य देशों द्वारा लागू व्यापार उपचार उपायों की मौजूदगी, अतिशेष क्षमताओं, संभावित व्यापार विपथन, भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता और पी यू सी के आयातों पर भारत द्वारा आधारभूत सीमा शुल्कों की कमी पर विचार करते हुए, शुल्क को समाप्त करने की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने/ पुनरावृत्ति की संभावना के प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं। प्रथम दृष्टया यह नोट किया गया कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन और शुल्क के जारी रहने/पुनरावृत्ति की संभावना है।

**निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत**

29. अतः आवेदकों के विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने पर तथा घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत संबद्ध देश के मूल के या वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद, पाटन के जारी रहने/उसकी पुनरावृत्ति और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना को सिद्ध करते हुए प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर और नियमावली के नियम के 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं ताकि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित, संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा की जा सके और यह जांच की जा सके कि क्या ऐसे शुल्क के समाप्त होने से पाटन और घरेलू उद्योग की क्षति को जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है।

**संबद्ध देश**

30. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच के लिए संबद्ध देश ब्राजील, चीन जन.गण., इंडोनेशिया, जापान, कोरिया आर.पी. और रूस हैं।

**जांच की अवधि**

31. याचिकाकर्ता ने जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2019 से 30 सितंबर, 2020 (18 महीने) प्रस्तावित की है और क्षति जांच अवधि में 2016-17, 2017-18 और 2018-19 और पी ओ आई की अवधियां शामिल हैं।
32. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में जांच की लंबी अवधि उचित है क्योंकि 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही में कोविड-19 के कारण व्यापार प्रभावित हुआ था। कथित पाटित आयातों के कारण उत्पन्न घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति और क्षति की संभावना का आकलन करना अधिक उचित होगा। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, 1 अप्रैल, 2019 से 30 सितंबर, 2020 की 18 महीने की जांच की अवधि (पीओआई) उचित प्रतीत होती है। क्षति जांच अवधि में अप्रैल, 2016- मार्च, 2017, अप्रैल, 2017- मार्च, 2018, अप्रैल, 2018- मार्च, 2019 और जांच की अवधि अर्थात् 1 अप्रैल, 2019 से 30 सितंबर, 2020 की अवधियां शामिल होगी।

**प्रक्रिया**

33. निर्णायक समीक्षा जांच में पाटन और क्षति की संभावना का विश्लेषण शामिल होगा।



34. संबंधित नियमावली नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

### **सूचना प्रस्तुत करना**

35. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों [adg13-dgtr@gov.in](mailto:adg13-dgtr@gov.in), [adv12-dgtr@gov.in](mailto:adv12-dgtr@gov.in), [dd18-dgtr@gov.in](mailto:dd18-dgtr@gov.in), [dd13-dgtr@gov.in](mailto:dd13-dgtr@gov.in), [dd19-dgtr@gov.in](mailto:dd19-dgtr@gov.in) पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए।
36. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
37. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
38. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
39. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे डी जी टी आर की अधिकारिक वेबसाइट अर्थात् <http://www.dgtr.gov.in/> को नियमित रूप से देखते रहें।

### **समय-सीमा**

40. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पतों [adg13-dgtr@gov.in](mailto:adg13-dgtr@gov.in), [adv12-dgtr@gov.in](mailto:adv12-dgtr@gov.in), [dd18-dgtr@gov.in](mailto:dd18-dgtr@gov.in), [dd13-dgtr@gov.in](mailto:dd13-dgtr@gov.in), [dd19-dgtr@gov.in](mailto:dd19-dgtr@gov.in) पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
41. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

### **गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

42. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।
43. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
44. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
45. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

46. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
47. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
48. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
49. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

#### **सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

50. डी जी टी आर की वेबसाइट पर सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची अपलोड की जाएगी। साथ ही उसमें उन सभी हितबद्ध पक्षकारों को उनके अनुरोधों का अगोपनीय पाठ ईमेल करने का अनुरोध किया जाएगा क्योंकि जारी वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध नहीं होगी।

#### **असहयोग**

51. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनंत स्वरूप, संयुक्त सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

### **MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

#### **INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st March, 2021

Case No.AD (SSR)-05/2021

**Subject: Initiation of sunset review investigation concerning imports of "Hot-Rolled flat products of alloy or non-alloy steel" from China PR, Japan, Korea RP, Russia, Brazil and Indonesia**

**F. No. 7/5/2021-DGTR.**—1. Indian Steel Association (hereinafter also referred to as the "Applicant" or "Petitioner") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") on behalf of Steel Authority of India Limited, JSW Steel Limited and ArcelorMittal Nippon Steel India Limited (hereinafter also referred to as the "Applicant producers") in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules") for initiation of sunset review investigation concerning imports of "Hot-Rolled Flat Products of Alloy or Non-Alloy Steel" (hereinafter referred to as the "subject goods" or "product under consideration"),

originating in or exported from China PR, Japan, Korea RP, Russia, Brazil and Indonesia (hereinafter also referred to as "subject countries"). The Applicant producers have provided the prescribed information in the Application.

2. The Applicant has alleged that dumping from the subject countries has continued even after the imposition of anti-dumping duty and that there is likelihood of continuation / recurrence of dumping and injury in case of cessation of duties. The Applicant has requested for extension of duties on imports of subject goods, originating in or exported from the subject countries.

### **Background**

3. The original anti-dumping investigation concerning imports of subject goods from subject countries was initiated on 11th April 2016 by the Designated Authority. The Designated Authority recommended provisional anti-dumping duty vide preliminary findings dated 1st August 2016, which was imposed vide Notification No. 44/2016-Customs, dated 8th August 2016. Pursuant to detailed investigation, the Designated Authority recommended imposition of definitive anti-dumping duties in the form of reference price on imports of the subject goods from the subject countries vide final findings notification no. 14/09/2016-DGAD, dated 10th April 2017. The recommendations of the Designated Authority were implemented vide Notification No.17/2017-Customs (ADD) dated 11th May 2017 (as amended by Corrigendum dated 16 May 2017) for a period of five years with effect from 8th August 2016. The existing duties will expire on 8th August 2021.

### **Product under consideration**

4. The product under consideration (hereinafter also referred to as "PUC") in the present investigation is "Hot-rolled flat products of alloy or non-alloy steel in coils of a width up to 2100mm and thickness up to 25mm, and Hot-rolled flat products of alloy or non-alloy steel not in coils (commonly known as sheets and plates) of a width upto 4950mm and thickness upto 150mm".
5. The following are not included in the scope of the product under consideration:
  - a) Hot-rolled flat products of stainless steel.
  - b) Hot-rolled flat products of steel which are electrolytically plated or coated with zinc.
  - c) Hot-rolled flat products of steel otherwise plated or coated with zinc.
  - d) Cladded steel.
6. The PUC includes products which are not further worked than hot-rolled and are flat products of iron, alloy or non-alloy steel, in prime or non-prime condition having 'as-rolled' edge or 'trimmed' edge or 'slit' edge or "milled" edge or "sheared" edge or "laser-cut" edge or "gas-cut" edge or any other type of edges. These products may be pickled or non-pickled (with or without skin-pass or tempering), slit or non-slit, normalized or un-normalized, ultra-sonically tested or untested or oiled or non-oiled etc. These products may be "as-rolled" or "thermo-mechanically rolled" or "thermo-mechanically controlled rolled" or "controlled rolled" or "normalized rolled" or "normalized" or subject to any other similar process. These products may have patterns in relief / chequered patterns of different types derived directly during hot rolling. These products may have been subjected to various processing steps like pickling, oiling, rewinding, recoiling, temper rolling, heat treatment, etc. These products may be sand blasted or shot blasted or subjected to similar processes. The PUC covers Hot Rolled flat sheets and plates of alloy or non-alloy steel, whether or not rolled from universal plate mill including reversible plate mill or hot strip mill or tandem mill or steckel mill or any other similar process with various type of rolling configuration including 2-High, 3-High, 4-High, cluster mill or any similar hot rolling process. The PUC includes sheets and plates produced either directly from the hot rolling process or cut / sheared from hot rolled coils.
7. The scope of the product under consideration in the present sunset review investigation is the same as in the original investigation.
8. The PUC is used in many applications and sectors such as automotive, oil and gas line pipes/exploration, cold-rolling, pipe and tube manufacturing, infrastructure and construction, general engineering & fabrication, earth-moving & mining equipment, storage tanks, low pressure heaters, capital goods including plant and process equipment for cement, fertilizer, refineries etc.
9. The PUC is classified under Custom Tariff Heading 7208, 7211, 7225 and 7226. The Customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.
10. It is noted that the domestic industry has not proposed PCN methodology in the sunset review petition. However, it is noted that in the original investigation, PCN methodology was proposed by the domestic industry, and the Authority determined Product Control Numbers (PCNs) in order to make a PCN-to-PCN

comparison for computing the dumping margin. The PCNs prescribed in the original investigation are given below, and the same is proposed to be used **for the present sunset review.**

PCN for Hot Rolled Flat Steel Products				
S.No.	Attributes	No. of Digits	Description	Code
1	Product Form	1	Coil	C
			Cut to length-Slit, Sheet, Plates	L
			Plate Mill Plate	P
2	Quality	4	Cold rolling/Galvanizing Quality	Q01Q
			Pipe and Tube quality	Q02Q
			High tensile including HSLA	Q03Q
			High Strength Structural Steel (YS 350 Mpa & above)	Q04Q
			Structural Steel (YS below 350 Mpa)	Q05Q
			Chequered quality	Q06Q
			Drawing/forming/flanging quality Steel	Q07Q
			API grade X52 and above quality Steel	Q08Q
			API grade below X52 quality Steel	Q09Q
			Quenched/Tempered Quality	Q10Q
			Corrosion Resistant Steel Quality	Q11Q
			Boiler/Pressure Vessel Quality	Q12Q
			Ship Building Quality	Q13Q
			LPG Cylinder quality	Q14Q
			Medium/High Carbon Steel Quality	Q15Q
			Silicon Electrical Steel	Q16Q
			Other Qualities not covered above	Q17Q
3	Thickness	1	upto 1.6 mm	T
			more than 1.6 mm upto 2mm	U
			more than 2 mm upto 10 mm	V
			more than 10mm upto 25 mm	W
			more than 25 mm upto 40mm	X
			more than 40 mm upto 100 mm	Y
			more than 100 mm upto 150 mm	Z
4	Width	1	upto 600mm	1

PCN for Hot Rolled Flat Steel Products				
S.No.	Attributes	No. of Digits	Description	Code
			more than 600mm upto 1500 mm	2
			more than 1500mm upto 2500 mm	3
			more than 2500mm upto 3000 mm	4
			more than 3000mm upto 4950 mm	5
5	Longitudinal Edges	2	As rolled	EB
			sheared/trimmed/milled/Gas-Cut etc.	ED
6	Surface Treatment/Surface preparation	1	Pickled	H
			Sand-blasted/shot blasted	I
			painted	J
			no surface treatment/no surface preparation	K
7	Heat Treatment	1	Un-Normalised	8
			Normalizing	9
<p>Example: A plate mill plate of chequered quality, 80 mm thick having width 750 mm with sheared edges in pickled form having unnormalized heat treatment</p> <p>Product PCN will be (11 digit): PQ06QY2EDH8</p>				

11. Interested parties may offer their comments, if any, on the PCN methodology within 10 days from the date of the initiation notice.

**Like article**

12. The applicant has claimed that the goods produced by the domestic industry are identical to the subject goods exported from the subject countries to India. Subject goods produced by the domestic industry are comparable to the imported goods from subject countries in terms of technical specifications, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the domestic industry are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

**Domestic industry**

13. The application has been filed by Indian Steel Association (Applicant) on behalf of the domestic producers. The following applicant producers have provided their costing and injury information for the purposes of the sunset review investigation:
- a. Steel Authority of India Limited
  - b. JSW Steel Limited
  - c. ArcelorMittal Nippon Steel India Limited.
14. The application is supported by (i) Tata Steel Limited and (ii) Tata Steel BSL Limited.

15. Of the three applicant producers, JSW Steel Ltd and ArcelorMittal Nippon Steel India Ltd have imported small quantities of the subject goods from the subject countries. As the volumes imported by them are small and their focus and area of operation continue to be manufacture of domestic like articles and not indulge in trading of subject goods, Authority considers it appropriate to treat them as part of the domestic industry.
16. Essar Steel India Ltd. was admitted to corporate insolvency resolution process by way of an Order dated 02.08.2017 passed by the National Company Law Tribunal, Ahmedabad. Pursuant to the procedure established by the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, ArcelorMittal India Pvt. Ltd. became the successful resolution applicant and with effect from 16.12.2019 took over the entire shareholding of the company. Pursuant to issuance of a fresh certificate of incorporation by the Registrar of Companies, the name of Essar Steel India Ltd. was changed to ArcelorMittal Nippon Steel India Ltd. with effect from 08.01.2020. The Company is incorporated in India under the Companies Act, 1956. It is a domestic producer of Hot Rolled Products (both in coil and not-in coil) and Cold Rolled Products and has significant production capacities in India and is in the process of further expansion. M/s. Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Japan has no direct shareholding in ArcelorMittal Nippon Steel India Limited but is a minority stakeholder in an intermediate holding company separated by several intervening independent corporate enterprises. ArcelorMittal Nippon Steel India Limited has not imported the subject goods from Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Japan during the POI. ArcelorMittal Nippon Steel India Limited is an independent, professionally managed company and does not reflect the individual interests of its shareholders. As a domestic producer, the very fact that it has come together with other domestic producers to seek the present sunset review evidences that it is not acting in a manner different from other domestic producers.
17. Therefore, the Authority has considered that the relationship has not affected the basic character of the ArcelorMittal Nippon Steel India Limited as producer of the like product in India. The Authority, therefore, considers ArcelorMittal Nippon Steel India Limited as eligible constituent of domestic industry under Rule 2(b) of the Rules.
18. As per evidence available on record, the applicant producers account for a major proportion in the domestic production of the like article in India. On the basis of information available, the Authority has considered the applicant producers as domestic industry within the meaning of the Rule 2(b) of the Rules.
19. It is noted that the Applicant Producers, along with the supporters, account for more than 50% of the total domestic production. In view of the above and after due examination, the Authority notes that the Applicant Producers constitute eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b), and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3), of the Rules supra.

#### **Basis of alleged dumping**

##### **Normal value**

##### **China PR**

20. The applicant has submitted that normal value for Chinese producers may be determined based on costs or domestic selling prices prevailing in China, only if the responding Chinese producers demonstrate that their cost and price information are based on market driven principles and allow for fair comparison in terms of Para 1 to 6 of Annexure I to AD Rules and that if none of the Chinese producers were able to demonstrate that they were operating under market economy principles, normal value for Chinese producers must be determined based on para 7 and 8 of Annexure I to Rules.
21. The Applicant has claimed that efforts were made to determine normal value on the basis of price or constructed value in a market economy third country, price from such a third country to other countries, including India. However, the applicant could not get reliable information regarding the same. The applicant has claimed that PUC has various grades and is classified under multiple HS codes, and because of these reasons it becomes difficult to get accurate reliable information regarding the same.
22. Therefore, the applicant has determined normal value for China PR on the basis of “any other reasonable basis” as per Para 7 of Annexure 1 to the Rules. In this regard, the applicant has claimed the normal value for China PR based on (a) International price of raw material, (b) Consumption norms, conversion costs and SGA costs on the basis of experience of the domestic industry, and (c) a reasonable profit.

##### **Normal value in Brazil, Indonesia, Japan, Korea RP, and Russia**

23. The applicant has claimed that they were able to get any documentary evidence or reliable information with regard to domestic prices of the subject goods in Brazil, Indonesia, Japan, Korea RP, and Russia. Also, because of the fact that there are multiple grades of PUC, and the PUC is classified under multiple HS codes at 8-digit level, the export price to an appropriate third country could not be obtained.

24. Under these circumstances, the applicant has constructed the normal value for all the subject countries based on (a) International price of raw material, (b) Consumption norms, conversion costs and SGA costs on the basis of experience of the domestic industry after making adjustment to duly reflect labour cost prevailing in the concerned subject country, and (c) a reasonable profit.
25. For the purpose of initiation, the Authority has considered the normal value claimed by the applicant.

#### **Export price**

26. There were no imports of HR in coils from Brazil, Indonesia and Russia and no imports of HR not in coils from Brazil and Russia during the period of investigation. The export price wherever available has been presented in the application on the basis of the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction-wise import data. Price adjustments have been made on account of ocean freight, inland freight, ocean insurance, commission, bank charges, port and handling expenses, and non-refundable VAT (only in case of China PR).

#### **Dumping margin**

27. Considering the normal value and export price determined as above, dumping margin determined is not only above de-minimis level but also significant. There is prima facie evidence that normal value of the subject goods in the subject countries is significantly higher than the net export price, thereby indicating that the subject goods originating in or exported from the subject countries have continued to be exported at dumped prices, in spite of antidumping duty in force.

#### **Likelihood of continuation / recurrence of dumping and injury**

28. There is *prima facie* evidence of likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of duty, considering the continued significant import quantities, increase in global steel capacity, lower steel demand around the world except India, significant unutilized capacities in subject countries, existence of trade remedial measures imposed by other countries against the subject countries, excess capacities, potential trade diversion, price attractiveness of Indian market and reduction of basic custom duties by India on imports of PUC. It is prima facie noted that there is likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of the anti-dumping duty.

#### **Initiation of sunset review investigation**

29. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, substantiating likelihood of continuation/recurrence of dumping of product under consideration originating in or exported from the subject countries and injury to the domestic industry, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 23 of the Rules, the Authority, hereby, initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

#### **Subject Countries**

30. The subject countries for the present sunset review investigation are Brazil, China PR, Indonesia, Japan, Korea RP, and Russia.

#### **Period of Investigation (POI)**

31. Petitioner has proposed the period from 1<sup>st</sup> April 2019 to 30<sup>th</sup> September 2020 (18 months) as the period of investigation (POI). The injury investigation period is 2016-17, 2017-18, 2018-19 and POI.
32. A longer period of investigation is appropriate in the present sunset review since trade in the first and second quarter of 2020-21 was impacted by Covid-19. A longer period would be more appropriate to assess the current injury and likelihood of injury to the domestic industry caused due to the alleged dumped imports. In view of the above, period of investigation (POI) of 18 months from 1<sup>st</sup> April 2019 to 30<sup>th</sup> September 2020 is deemed appropriate. The injury investigation period will cover the periods April 2016 - March 2017, April 2017 - March 2018, April 2018 - March 2019 and the period of investigation i.e. 1<sup>st</sup> April 2019 to 30<sup>th</sup> September 2020.

#### **Procedure**

33. The sunset review investigation will undertake likelihood analysis of dumping and injury.

34. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules shall be mutatis mutandis applicable in this review.

**Submission of Information**

35. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses [adg13-dgtr@gov.in](mailto:adg13-dgtr@gov.in), [adv12-dgtr@gov.in](mailto:adv12-dgtr@gov.in), [dd18-dgtr@gov.in](mailto:dd18-dgtr@gov.in), [dd13-dgtr@gov.in](mailto:dd13-dgtr@gov.in), [dd19-dgtr@gov.in](mailto:dd19-dgtr@gov.in).
36. The known producers/exporters in the subject countries, Government of the subject countries through their Embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
37. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
38. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a nonconfidential version of the same available to the other parties.
39. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

**Time Limit**

40. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses [adg13-dgtr@gov.in](mailto:adg13-dgtr@gov.in), [adv12-dgtr@gov.in](mailto:adv12-dgtr@gov.in), [dd18-dgtr@gov.in](mailto:dd18-dgtr@gov.in), [dd13-dgtr@gov.in](mailto:dd13-dgtr@gov.in), [dd19-dgtr@gov.in](mailto:dd19-dgtr@gov.in) within 30 days from the date of receipt of the notice as per as Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
41. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

**Submission of information on confidential basis**

42. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non- confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
43. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
44. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
45. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
46. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The nonconfidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
47. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or in summary form, it may disregard such information.
48. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.



49. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**Inspection of Public File**

50. A list of interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all interested parties since the public file will not be accessible physically due to ongoing global pandemic.

**Non-cooperation**

51. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Jt. Secy. & Designated Authority